मध्य प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

रुचि वर्धन बनीं भोपाल ग्रामीण आईजी शाजापुर और शहडोल के एसपी बदले

रुचि वर्धन मिश्रा, आईपीएस

मिथिलेश शुक्ला, आईपीएस

सिमाला प्रसाद, आईपीएस

संजय कुमार अग्रवाल, आईपीएस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शुक्रवार देर रात 9 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत भोपाल ग्रामीण, सागर और नर्मदापुरम को नए आईजी मिलने के साथ ही दो जिलों के पुलिस कप्तान (एसपी) भी बदले गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में आईजी प्रशासन के पद पर तैनात रुचि वर्धन मिश्रा को अब आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, नर्मदापुरम जोन के आईजी मिथिलेश शुक्ला को अब सागर रेंज का फुल टाइम आईजी बनाया गया है; वे हिमानी खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद से सागर रेंज का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। मिथिलेश शुक्ला के सागर जाने के बाद रिक्त हुए नर्मदापुरम जोन के आईजी पद पर चंद्रशेखर सोलंकी को पदस्थ किया गया है, जो वर्तमान में इंदौर एसएएफ रेंज में सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा, आईजी एससीआरबी हरिनारायण चारी मिश्रा को स्थानांतरित करते हुए पुलिस मुख्यालय में आईजी प्रशासन की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शाजापुर और शहडोल के एसपी बदले, सिमाला प्रसाद बनीं खरगोन डीआईजी

इस फेरबदल में दो जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को भी बदला गया है। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि उनके स्थान पर शहडोल के निवर्तमान एसपी रामजी श्रीवास्तव को एआईजी बनाकर पुलिस अकादमी भौंरी भेजा गया है। इसी तरह, प्रियंका शुक्ला को शाजापुर जिले का नया एसपी बनाया गया है, जबकि शाजापुर के मौजूदा एसपी यशपाल सिंह राजपूत का तबादला करते हुए उन्हें पुलिस अधीक्षक रेल, इंदौर की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही, आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद की पदोन्नति के बाद उन्हें डीआईजी खरगोन रेंज के पद पर नई पदस्थापना दी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारियां

तबादला सूची में कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को उनकी वर्तमान भूमिकाओं के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ स्पेशल डीजी दूरसंचार (पीएचक्यू) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, इंदौर ग्रामीण जोन के आईजी अनुराग को अब अपने मौजूदा कार्य के साथ-साथ आईजी एसएएफ इंदौर रेंज और आईजी आरएपीटीसी इंदौर के पदों का भी अतिरिक्त जिम्मा संभालना होगा। राज्य सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कसावट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश में बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, दो बच्चों की मौत, सड़कें-पुल डूबे

मानसून का कहर : जनजीवन अस्त-व्यस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में मानसून ने शनिवार को रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी-नाले उफान पर हैं, पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। अनेक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जबकि निचले इलाकों में घरों, स्कूलों और खेतों में पानी भर गया है।

कई स्थानों पर तेज बहाव के बीच वाहन फंस गए, वहीं एक जगह उफनती नदी में ट्रैक्टर पलट गया। सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में अति भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।हरदा जिले में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों का संपर्क कट गया है। ग्राम मांदला के पास कालीमाचक नदी का पानी पुल से करीब तीन फीट ऊपर बह रहा है, जिसके चलते नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आवागमन में परेशानी झेल रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए रखी है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सीहोर जिले के आष्टा ब्लॉक में लगातार बारिश के कारण पार्वती, पपनास और नेवज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बापचा दोनिया गांव में दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिजन दोनों बच्चों को तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं खाचरोद, मेहतवाड़ा, मैना, कोठरी, भंवरा, बागैर, सिंगारचोरी, हराजखेड़ी, ढकनी और मुगली सहित कई गांवों में घरों में पानी घुस गया है। बड़घाटी-रामापुरा पंचायत क्षेत्र में बाढ़ का पानी खेतों तक पहुंचने से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। अमलाहा-गोलूखेड़ी मार्ग पर अजनाल नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने से यातायात प्रभावित रहा। खंडवा जिले में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले कई घंटों से जारी बारिश के बीच रेड अलर्ट घोषित किया गया है और चार इंच तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। किल्लौद ब्लॉक के ग्राम गरबड़ी स्थित नाले में अचानक आई बाढ़ से खिरकिया मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को उफनते नालों और पुलों को पार नहीं करने की चेतावनी दी है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और राहत दल लगातार निगरानी कर रहे हैं।

पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र भी लगातार वर्षा से बेहाल हैं। ओंकारेश्वर सहित आसपास के क्षेत्रों में छोटे-बड़े नदी-नाले उफान पर हैं तथा कई पुल-पुलियों के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। ग्रामीण इलाकों की गलियां नदी जैसी दिखाई दे रही हैं और कई संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। इसके बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर पानी से लबालब पुलों और पुलियों को पार करते नजर आए।

प्रशासन और स्थानीय लोगों की समझाइश के बावजूद इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ओंकारेश्वर नगर में बारिश का पानी घाटों की ओर तेज वेग से बहता दिखाई दिया, जिससे प्राकृतिक झरनों जैसा दृश्य बन गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेशवासियों, सहकारी समितियों के सदस्यों और सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सहकारिता आंदोलन को देश की समृद्धि का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र लगातार सशक्त हो रहा है और विकास की मुख्यधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विस्तार में सहकारिता की अहम भूमिका है। राज्य सरकार दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत बनाने, पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रदेश को देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार गौशालाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहयोग दे रही है तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

बूथ लेवल अधिकारी लोकतंत्र की नींव हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सराहना, मध्यप्रदेश को बताया देश के लिए आदर्श

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि बूथ लेवल अधिकारी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य उत्कृष्ट ढंग से संपन्न करने पर मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने पारदर्शिता, दक्षता और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो देश के लिए अनुकरणीय है।

उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्थाओं में शामिल है। मतदाता सूची निर्माण से लेकर मतदान और मतगणना तक प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने बताया कि भारत इस वर्ष इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है, जो देश की चुनावी व्यवस्था की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान वृद्धजन, दिव्यांगजन, प्रवासी श्रमिकों तथा वंचित वर्गों तक मतदाता सेवाएं पहुंचाने पर है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि जनजागरूकता के लिए समाचार पत्र, आवृत्ति प्रसारण, सामाजिक माध्यम, व्हाट्सएप तथा पंचायत स्तर तक व्यापक अभियान चलाए गए।

उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों को लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी बताते हुए कहा कि वे घर-घर जाकर नए मतदाताओं का पंजीयन, मृत, स्थानांतरित और दोहराए गए नामों का निराकरण तथा मतदाता सूची को अद्यतन रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विशेष रूप से दूरस्थ आदिवासी और वन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के योगदान की उन्होंने सराहना की।

कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कहा कि मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

मप्र के इंदौर में 'पीएम ई-बस सेवा' का आई-14 रूट पर ट्रायल शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम ई-बस सेवा' के अंतर्गत शनिवार से रूट नंबर आई-14 पर ट्रायल शुरू हो गया है। इस रूट पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रायल प्रारंभ हुआ है। यह रूट राऊ रंगवासा से रणजीत हनुमान, राजवाड़ा और बंगाली स्क्वायर होते हुए कनाड़िया बाइपास तक है।

इंदौर को मिलीं 150 अत्याधुनिक ई-बसें: भारत सरकार की इस विशेष योजना के अंतर्गत इंदौर शहर को कुल 150 हाई-टेक इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। 9 मीटर लंबाई की यह बसें पूर्णतः वातानुकूलित हैं। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आधुनिक सुविधाओं को समाहित किया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत आज से 10 बसों का ट्रायल रन प्रारंभ किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे बढ़ाकर 150 बसों तक किया जाएगा।

सुरक्षा और हाई-टेक सुविधाओं से लैस : यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए इन बसों में विश्वस्तरीय तकनीकों का समावेश किया गया है। सिक्योरिटी सिस्टम एवं लाइव मॉनिटरिंग सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे और 'पैनिक बटन' की सुविधा हैं। इन बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों का फीड (फुटेज) सीधे सेंट्रल कंट्रोल रूम में लाइव देखा जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग और भी बेहतर होगी।

इंटेलिजेंट मैनेजमेंट बसों के रियल-टाइम संचालन, ट्रैकिंग और शेड्यूलिंग के लिए आईटीएमएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जिसका मॉनिटरिंग एआईसीटीएस एल कार्यालय एवं नायता मुंडला डिपो स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाएगी। डिजिटल टिकटिंग डिजिटलीकरण के प्रति जागरूकता एवं कैशलेस यात्रा को बढ़ावा के लिए बसों में डिजिटल किराया संग्रहण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

स्मार्ट स्टाफ : 'कोच कैप्टन' और 'डिजिटल असिस्टेंट' संभालेंगे कमान : परिवहन के इस आधुनिक ढांचे को संचालित करने के लिए पारंपरिक ड्राइवर और कंडक्टर के स्थान पर अब विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं वर्दीधारी 'कोच कैप्टन' और 'डिजिटल असिस्टेंट' की नियुक्ति की जा रही है। जो यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय सफर का अनुभव कराएंगे।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था : बसों में व्हीलचेयर असिस्टेंस सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दिव्यांग नागरिकों को बस में चढ़ने और उतरने में सुगमता व सुविधा होगी।

5,017 नव-नियुक्त शिक्षकों को मिले नियुक्ति आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 5,017 नव-नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों, खेल तथा गायन-वादन के 4,067 तथा प्राथमिक शिक्षक के खेल, नृत्य और गायन-वादन वर्ग के 950 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग ने तीन और चार जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव-नियुक्त शिक्षक अपने ज्ञान, समर्पण और कार्यकुशलता से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और समाज के भविष्य को दिशा देने वाले होते हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों से निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आह्वान किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेशवासियों, सहकारी समितियों के सदस्यों और सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सहकारिता आंदोलन को देश की समृद्धि का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र लगातार सशक्त हो रहा है और विकास की मुख्यधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विस्तार में सहकारिता की अहम भूमिका है। राज्य सरकार दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत बनाने, पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रदेश को देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

साइबर ठगी पर हाईकोर्ट सख्त, एसपी समेत तीन अधिकारियों को किया तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने 6.24 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले की जांच में हो रही धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जबलपुर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गोराबाजार थाना प्रभारी और मामले के विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई में मूल केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना को एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। अदालत ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि जब जांच एजेंसी के पास आरोपियों से संबंधित पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, तब भी कार्रवाई में इस तरह की सुस्ती स्वीकार्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका सबसे अधिक असर आम नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को अगली सुनवाई में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में अब तक की गई सभी जांच संबंधी कार्रवाइयों का ब्यौरा देना होगा। अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कितने स्थानों पर दबिश दी गई, किन-किन राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया, उनके साथ क्या पत्राचार हुआ, कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए तथा जांच पूरी होने की संभावित समय-

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के पुलिस महानिदेशकों को भी पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (गृह) को भी मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया है। अदालत का मानना है कि चूंकि मामला कई राज्यों से जुड़ा है, इसलिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

समीक्षा *मप्र विधानसभा अध्यक्ष तोमर की अध्यक्षता में गठित समिति ने 11 बिंदुओं पर की अनुशंसाएं...*

सात राज्यों को विस अध्यक्षों ने लोस अध्यक्ष को सौंपी अनुशसाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की अंतिम बैठक शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा कोलकाता में हुई। तीन समीक्षा बैठकों में चर्चाओं के बाद समिति ने 11 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसाएं की हैं। इन सिफारिशों के साथ समिति का प्रतिवेदन सात राज्यों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा।

प्रतिवेदन सौंपते समय सात राज्यों मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राजस्थान विधानसभा वासुदेव देवनानी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र नाथ बोस अध्यक्ष, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिंग्मा नोर्बु शेरपा तथा ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी कार्यवाही में वित्तीय सहित तदर्थ समितियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। इस

भूमिका को अधिक स्पष्ट और समर्थ बनाने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई थीं। समिति में 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के राज्य विधान मण्डल शामिल हैं। समिति की पहली बैठक मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल में 14 जुलाई, 2025 को एवं दूसरी बैठक राजस्थान विधानसभा, जयपुर में 5 मई, 2026 को हुई थी। कोलकाता में तीसरी और अंतिम बैठक में विधानसभा समितियों के संबंध में विमर्श हुआ।

पीठासीन अधिकारियों की समिति ने समितियों की बैठकों की संख्या, सभा समिति के सदस्यों के कार्यकाल, सभा समितियों के कोरम, सभा समितियों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, विधेयकों को समितियों को संदर्भित किए जाने, सभा समितियों के प्रतिवेदनों पर चर्चा, सभा समितियों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थित सुनिश्चित करने, बजट परीक्षण के लिए स्थायी समितियों के गठन, सलाहकार समितियों के गठन, समितियों के अध्ययन दौरे के पश्चात की जाने वाली कार्यवाहियों आदि पर विचार कर 11 बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं।

शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये के अडानी डिफेंस प्लांट का होगा शिलान्यास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार, 5 जुलाई को शिवपुरी में अडानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। इस अवसर पर दोनों नेता 211.29 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। प्रदेश सरकार के अनुसार यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती देने के साथ मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होने से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com